[شری محمد خلیل الرحمان]
صرف هندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہے - لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کرناٹک کی جانب سے اور پھر حکومت هند کی جانب سے اسکی سرپرستی کی جائے اور اسکو انکریج کیا جائے -

وائس چیرمین سر - پچھلے دس سالوں سے هم یہ دیکھ رہے هیں کہ بیدری جو صنعت ہے - اس سے جو مال بنتا ہے اسکی قیمت میں تو کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا ہے - مگر جو را میٹیریل ہے خاص طور سے سلور اور زنکہ - انکی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے - دس سال پہلے جو سلور کی قیمت ۳۵-۳۶ روپئے فی ۱۰ گرام تھی وہ قیمت ۸۰-۸۲ روپئے پرتی دس گرام ہو گئی ہے - اور اسی طرح سے زنک جو ۱۸-۲۰ بیس روپئے فی کلو گرام تھی اب اسکی قیمت جاکر ۴۰-۴۵ روپئے تک فی کلو گرام ہو گئی ہے - مگر جو فنشڈ گڈس هیں اسکی قیمت میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا ہے - دیکھا یہ جا رہا ہے کہ صنعت سے جو وابستہ لوگ هیں وابستہ کاریگر هیں - وہ پوری طرح سے گھاٹے میں هیں - انکے معاشی موقف بری طرح متاثر ہو رہا ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف حکومت توجہہ کرے - میں حکومت هند سے اور پھر حکومت کرناٹک سے یہ مطالبہ کرونگا کہ بیدری هینڈی کرافٹ کی جو صنعت ہے - اسکی طرف وہ خاص توجہہ کریں - اور کچھ اس قسم سے وہاں کے کاریگروں کو سبسڈی دیں - جس سے سستی قیمت پر سلور اور زنک خرید سکیں - اور دستکاری کو قائم رکھ سکیں - اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ انکے بچوں کیلئے اچھی قسم کی ایجوکیشن کی فیسیلٹی دی جئے - انکے لئے مکانات اور هاؤسنگ کی فیسیلٹیز هوں -

آخر میں میں حکومت هند سے یہ مطالبہ کرونگا کہ وہ خود بھی اس طرف توجہہ کرے اور پھر حکومت کرناٹک کو بھی اس بات کی هدایت دے کہ بدری هینڈی کرفٹ کے تعلق سے خاص خیال رکھا جائے- شکریہ -]

Red-tapism in Public Sector Undertaking

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान इतिहास के उन पन्नों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिन्हें इतिहास बनाने वाले ने स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से लिखा था ताकि भावी पीढ़ी इंसानियत के, मानवता के मूल्यों की कीमत समझ सके।

23 मार्च, 1931 का वह दिन, जब कानपुर शहर सांप्रदायिक उन्माद की आग की लपटों से सुलग रहा था तो उस समय इन आग की लपटों की परवाह न करते हुए वह शख्स उन्मादित दंगाइयों के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया था और उन्हें ललकारते हुए कहा था— "मेरे मरने से आप लोगों के हृदय की प्यास बुझती है तो अच्छा है, मैं यहीं अपना कर्तव्य पालन करते हुए आत्म-

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

समर्पण कर दूं।" और इस तरह सांप्रदायिकता की घिनौनी नफ़रत की आग को बुझाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वे दंगाइयों के हाथों मारे गए, लेकिन एक ऐसी मौत कि जिस मौत पर ज़िंदगी भी रश्क करे। इसीलिए महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर यंग इंडिया में लिखा—"गणेश शंकर विद्यार्थी को ऐसी मृत्यु मिली, जिस पर हम सबको स्पर्धा हो। उनका खून अंत में दोनों मजहबों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करेगा। उन्होंने जिस वीरता का परिचय दिया है, वह अंत में पत्थर से पत्थर को भी पिघला देगी और पिघला कर एक में मिला देगी।" पंडित नेहरू ने कहा था—"मर कर जो सबक उन्होंने सिखाया, वह हम वर्षों जिंदा रहकर क्या सिखायेंगे।"

सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत कबूल करने वाले, कानपुर से निकलने वाले प्रख्यात पत्र "प्रताप" के संपादक, हमारे प्रेरणा स्तंभ गणेश शंकर विद्यार्थी का यह जन्म-शताब्दी वर्ष है। लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों की जन्म शताब्दी आदि... **(व्यवधान)** ...

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR (Gujarat) : There is no Minister or Leader of the House here. It is an insult to the House.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Has the Government failed? I believe the Government is not there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Please wait for him.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हाऊस बिना मिनिस्टर के हो।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : यह सदन का अपमान है। यह पहला मौका नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकये हुए हैं।

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): I move a motion that we unanimoulsy accept Shri Virendra Verma as the Minister representative of the Government.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Let the House be adjourned until the Minister comes.

श्री सुरेश कलमाडी (महाराष्ट्र) : वे आप लोगों को नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने बना दिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मानव संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों की जन्म शताब्दी आदि के बारे में सरकार की योजनाओं की चर्चा है, लेकिन उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की कोई चर्चा नहीं है। कानपुर में उनकी बलिदान स्थली पर आज तक कोई स्मारक नहीं बन पाया है।

सन् 1931 में पंडित नेहरू ने यह ऐलान किया था कि जिस स्थान पर विद्यार्थी जी का खून गिरा है, वहां एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देश आजाद हो गया और अब आजादी के 43 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वहां कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। यहां तक कि सन् 1962 में नेहरू जी के प्रयास से कानपुर नगर पालिका ने 31 मार्च को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि साम्प्रदायिक एकता और सौहार्द के लिए वह उस बलिदान के स्थल पर एक स्मारक बनाएगी और इस के लिए दो लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया। सन् 1969 में जब खान अब्दुल गफ्फार खां एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कानपुर गए तो उन्होंने विद्यार्थी जी की बलिदान स्थली पर जाने की इच्छा जाहिर की। अधिकारियों की लाख आना-

कानी के बावजूद वे जिद करके उस स्थान पर पहुंचे और उस समय वे उस बलिदान स्थली को देखकर फूट- फूटकर रोने लगे थे। भारत के लिए इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है?

इसके बाद 25 मार्च, 1970 को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनवर अहमद ने इस स्मारक का शिलान्यास भी किया, लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ जो जनता को धोखा देने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए तमाम शिलान्यासों का होता रहा है। छः महीने बाद लोग शिलान्यास का पत्थर भी उखाड़ कर ले गए।

कानपुर शहर आज फ़िर साम्प्रदायिकता की चपेट में है। साम्प्रदायिकता की आंधी के विरूद्ध सीना तानकर खड़े होने वाले व्यक्ति की आज कानपुर वासियों को बड़ी जरूरत है। विद्यार्थी जी की बलिदान स्थली पर यदि स्मारक बहुत पहले ही बन गया तो वह स्मारक साम्प्रदायिकता के विरूद्ध धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का एक प्रेरणास्थल होता, लेकिन अफ़सोस कांग्रेस की सरकारें इस दिशा में अंधी बनी रहीं।

अब विद्यार्थी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह साम्प्रदायिकता के विरूद्ध संघर्ष की विद्यार्थी जी की शानदार परम्परा को किस तरह आगे बढ़ाए। स्वतंत्रता संग्राम तथा साम्प्रदायिकता के विरूद्ध विद्यार्थी जी की गौरवशाली भूमिका को आज पूरी शक्ति के साथ जनता के सामने लाने की जरूरत है।

मैं आशा करती हूं कि नई सरकार विद्यार्थी जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी शहादत का उचित सम्मान करेगी।

Hardships being faced by Doctors

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Thank you Mr. Vice-Chairman. Through this special metion I wish to draw the attention of the Government and this House to the hardships that have been faced by the members of the medical profession in this country today. There was a time not long ago wh n the doctors in this country were called members of a noble profession. But today the wrong policies of the Government and a callous attitude of the administration towards the hardships being faced by the doctors is creating a very erroneous public image which is doing a double harm. On the one hand justice is not being given to the doctors and on the other, the people are having a quality of medical care which could be improved and because the providers of the medical services are in a state of harassed mind and body, the people are suffering today on account of the deterioration, on the quality of medical services. In a short time, I cannot narrate all the things but I want to give one or two glaring examples. See the conditions of those doctors who are serving the Government. They take to the democratic methods, form associations, but nobody listens to them till they go on strike. They went on strike in 1987. It was a long and very painful strike, the people suffered and so also the image of the medical profession. But at the end of the strike, there was a Memorandum of Settlement which was signed between the doctors and the Government. Two years have have elapsed but nothing was done to that Memorandum of settlement. In the year 1989 again doctors went on strike just to press their demands that what was agreed to by the Government in 1987 should be implemented now and again there was a long drawn negotiation and again the Memoradnum of Settlement signed for the second time between the Government and doctors has not been implemented. Do we want another strike? I do not know, Sir. The problem is that the Ministers change and unfortunately, in the Ministry of Health, there have been manychanges in the last